

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

राजेन्द्र कुमार मीना

व्याख्याता अर्थशास्त्र

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज.)

प्रस्तावना - 'यदि भारत को जीवित रहना है तो सबसे पहले निचले (ग्रामीण) स्तर से कार्य शुरू करना होगा यदि इसकी स्थिति खराब होगी तो बाकी के सभी स्तरों पर किया गया कार्य निष्फल होगा।'

गाँधी जी की उक्त धारणा कि ग्रामीण विकास पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है इस दृष्टि से कृषि विकास की भूमिका और बलवती हो जाती है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मानव संख्या कृषि और कृषि कार्यों पर अवलम्बित ही नहीं आश्रित भी है। आज भी देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि है। आजादी के समय जी. डी. पी. में कृषि का 50 प्रतिशत अंश था और वर्तमान में 22 प्रतिशत अंश कृषि का है। इसका मुख्य कारण कि आज देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का सातवाँ स्थान क्रय शक्ति समता की दृष्टि से तीसरा स्थान रखने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा असंगठित व्यवसाय है। यही नहीं कृषि राष्ट्रीय आय का स्रोत, रोजगार एवं जीवनयापन का प्रमुख साधन औद्योगिक विकास, वाणिज्य एवं व्यापार का आधार भी है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता से पूर्व भी कृषि विकास के प्रयास होते रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को सर्वोपरी माना गया इसी कारण प्रथम पंचवर्षीय (1951) से लेकर आज तक 12 पंचवर्षीय (2012 से 2017) योजना तक में किसी न किसी रूप में कृषि विकास के लिए प्रयास जारी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँवों के विकास से ही देश का विकास संभव है अर्थात् कृषि विकास से ही देश का विकास संभव है।

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का अध्ययन करना है।

परिकल्पना - कृषि ग्रामीणों की आय का एक बड़ा साधन रोजगार प्राप्त करने का स्रोत, ग्रामीण उद्योग धंधों का आधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ एवं विकास की कुंजी में कृषि कैसे सशक्त बनकर ग्रामीणों को अपने विकास के लिए सार्मथ्य बनाकर विकास की ओर ले जा सकती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बनावट दो क्षेत्रों से मिलकर बनी है (1) कृषि क्षेत्र इसमें खाद्य फसलें एवं व्यावसायिक फसलें आती हैं (2) गैर कृषि क्षेत्र इसमें ग्रामीण क्रियाकलाप आते हैं। अर्थात् पशुपालन डेरी व्यवसाय मुर्गीपालन, मत्स्यपालन तथा वानिकी आदि। जब कृषक बेकार बैठे रहते हैं तो इन कार्यों से जुड़कर अल्प बेरोजगारी को दूर करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है और 10 में से 7 व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। भारत में 6 लाख 40 हजार 930 गाँव हैं। गाँव में साक्षरता का प्रतिशत 67.8 प्रतिशत है जिसमें 57.9 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर और 77.2 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं और भारत में कुल श्रमिकों का 54.6 प्रतिशत भाग कृषि व उससे संबंधित व्यवसाय में लगा है। इसलिए आज भी भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की महती भूमिका है इसकी भूमिका के निम्न कारण हैं-

1. आय एवं आजीविका का प्रमुख साधन - कृषि उत्पादन का ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है कृषि का स्तर अच्छा है तो रहन-सहन का स्तर अच्छा होगा इसके विपरीत कृषि स्तर अच्छा नहीं तो रहन-सहन का स्तर भी अच्छा नहीं होगा कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत गांवों में रहता है, जहां के लोगों की जीविका का साधन कृषि है और देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 54.6 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा है जिसमें 24.6 प्रतिशत कृषक तथा शेष कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। 5 अर्थात् 30 प्रतिशत कृषकों के पास अपनी जमीन ही नहीं है इसके कई कारण हैं जैसे - कुटीर एवं हस्तकला उद्योगों का पतन, ऋण गृहस्तता, अनार्थिक जोते, जनसंख्या वृद्धि, सरकारी फार्मों पर खेती, बेरोजगारी, कृषि की अनिश्चितता इत्यादि ये सब कारणों से भूमिहीन कृषक दूसरों की खेतों में काम करके जीविका चलाते हैं। इस तरह जीविका चलाने वाले कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए भी सरकारी प्रयास एवं सुझाव जारी हैं। सरकार भी कृषि श्रमिकों के लिए उपाय कर रही है उसमें प्रमुख है - न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, मुफ्त प्लाट, भूमि की व्यवस्था, बंधुआ मजदूर प्रथा का अंत कृषि [सेवा समितियों की स्थापना, ऋण मुक्ति कानून क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, श्रमिक सहकारिताओं का गठन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि। सभी प्रयासों के बावजूद भी आज तक की स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास को समउन्नत नहीं कर पाए हैं। यही नहीं कृषक आज भी परम्परागत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई की असुविधा, उत्तम प्रकार के बीज का अभाव, विपणन, भण्डारण की असुविधा, वित्त की कमी और बहुत सारे कारण हैं, जो ग्रामीण कृषि समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं ये सारी बातें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विद्यमान हैं और एक मात्र आय और जीविका का साधन होते भी कृषि की दयनीय स्थिति उनके विकास के मार्ग को पीछे की ओर ले जाती है।

2. रोजगार का स्रोत - कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत है, देश की कार्यशील जनसंख्या (54.6 प्रतिशत) प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी है और भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार 100 में 48.17 व्यक्ति कृषि से रोजगार प्राप्त करते थे और जिनके पास 'वर्तमान समय में भूमि सिंचाई के साधन पूंजी आदि साधन उपलब्ध हैं तो वे खाद्यान्न, अंगूर, फल, दाल, सब्जियों, फूल, नगदी फसलें कपास, गन्ना, जूट, तम्बाखू आदि में कृषि फार्म, डेयरी फार्म, फल उद्यान, चाय काफी, रबर के बाग, नर्सरी बगीचों का प्रबंध, मुर्गी व सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़े पालना, मछली पालन, भेड़ पालन आदि करके ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं 18 और कृषि एवं गैर कृषि तरीकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं। नई कृषि तकनीक से ग्रामीण जनसंख्या अपने रोजगार को बढ़ाने में सक्षम हो सकती है।

3. खाद्यान्न एवं चारे की पूर्ति - ग्रामीण भारत में कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है खाद्यान्न उत्पादन भारत में आशातीत रूप से बढ़ रहा है। 1950-57 में उत्पादन 50.8 मिलियन टन था जो 2013-14 में बढ़कर 264.4 मिलियन टन हो गया यही नहीं वाणिज्यिक फसलें (जिसमें तिलहन कपास, जूट, गन्ना एवं आलू) का उत्पादन भी 2013-14 में बढ़कर क्रमशः 32.4, 529.0, 10.8, 3.484.6 एवं 464.0 लाख टन हो गया। खाद्यान्न फसलें (चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल) के उत्पादन में 1950.51 से 2013-14 में क्रमशः एक अनुपात के अनुसार चावल में 3 गुने से ज्यादा वृद्धि, गेहूँ 5 गुने से ज्यादा वृद्धि, ज्वार में 3 गुना वृद्धि, बाजरा में 5 गुने वृद्धि, मक्का में 4 गुना वृद्धि एवं दालों में 2 गुने से कम वृद्धि हुई। इस प्रकार देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर होता जा रहा है। इसलिए कृषि की भूमिका सर्वोपरी है। इसी तरह 52 करोड़ पशुओं का चारा भी कृषि से ही प्राप्त होता है इस प्रकार कृषि जन एवं जानवरों के जीवन का आधार है।

4. आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख निर्धारक - ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं सम्पूर्ण भारत के आम रोजगार अन्य आर्थिक तत्व कृषि क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होते हैं। कृषि में हुई प्रगति ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति को परिलक्षित करती है क्योंकि कृषि ही अर्थव्यवस्था में संतुलन का कार्य करती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार, संकुचन, गतिशीलता, निष्प्रभाहता प्रगति, प्रतिगति सब कृषि की देन है कृषि के द्वारा ही 54.6 व्यक्तियों को रोजगार

एवं 19 प्रतिशत आय में सहायक है इसीलिए जब उत्पादन में कमी होती है तो ग्रामीण ही नहीं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वोच्च स्थान है।

5. उद्योगों का आधार - कृषि देश के अनेक छोटे-बड़े तथा घरेलू उद्योगों का आधार है सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन 1950-51 में 4.215 मिलियन वर्गमीटर था जो 2011-12 में बढ़कर 30.570 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। चीनी का उत्पादन 2000-2001 में 185.19 लाख टन था जो 2012-13 में बढ़कर 248.00 लाख टन हो गया और 2017 में यह उत्पादन 5.21 मिलियन मेट्रिक टन रहने की संभावना है। 10 जूट का उत्पादन भारत में विश्व का 40 प्रतिशत होता है 9 लाख 70 हजार हेक्टेयर में उत्पादन होता है 3 लाख यक्तियों को रोजगार एवं 40 लाख परिवारों का भरण-पोषण का साधन है।" भारत की काफी दुनिया भर की अच्छी गुणवत्ता की काफी मानी जाती है। यह दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी (8200 टन) क्षेत्रों में होती है इसका 80 प्रतिशत भाग निर्यात कर दिया जाता है। 12 रबर के लिए भारत का विश्व में चौथा स्थान है। इसी प्रकार चाय का उत्पादन जैविक खेती के कारण और बढ़ गया है चाय का निर्यात भारत विश्व के 80 से अधिक देशों को करता है। '3 इन सब उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि से ही होती है ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में चावल, आटा, दाल, तेल आदि के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से ही होती है।

6. परिवहन के साधनों की आय का स्रोत- देश में परिवहन की आय का साधन भी कृषि ही है क्योंकि कृषि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए रेल, मोटर, और वर्तमान में परिवहन के सभी साधन को आय का बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त गांवों देहातों से मंडियों तक कृषि पदार्थों को पहुंचाने में परिवहन के परम्परागत एवं आधुनिक साधनों की आय का आधार भी कृषि है।" कृषि के उत्पादन बढ़ने से ही परिवहन के क्षेत्र की आय बढी है।

7. विदेशी व्यापार में महत्व - देश के कुल निर्यात का लगभग 12.4 प्रतिशत भाग कृषि पदार्थों एवं कृषि से संबंधित पदार्थों का होता है। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुएं निर्यात करता है एवं 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुओं का आयात करता है।" इसमें प्रमुख कृषि उत्पाद है - चाय, काफी, चावल, काजू, गरम मसाले, कपास इत्यादि । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, मूंगफली चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है चावल, कपास, गन्ना तथा जूट में द्वितीय स्थान एवं तम्बाकू में तृतीय स्थान एवं प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पाँचवा स्थान है इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता सबसे अधिक है।

8. सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव- औद्योगिक प्रगति का आधार, सामाजिक व राजनैतिक महत्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से केवल आय, की रोजगार, खाद्यान्न की पूर्ति, उद्योगों को कच्चा माल, ही प्राप्त नहीं होता वरन् सामान्य मूल्य स्तर पर भी कृषि का प्रभाव पड़ता है औद्योगिक स्तर भी कृषि पर निर्भर करता है और कृषि की व्यावसायिक स्थिरता सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करती है।

उपरोक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का विश्लेषण करने के पश्चात् यह टिप्पणी निष्पादित की जा सकती है कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण समृद्धि एवं विपन्नता का चित्रण प्रस्तुत करती है। कृषि की भूमिका से संबंधित मेरे सुझाव निम्न हैं ।

1. सर्वप्रथम तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन आईएवाई पीएमजीएसवाई एनआर एलएम महिला सशक्तिकरण एसजीएसवाई, आरएच 16 जैसी न जाने कितनी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं उनकी जानकारी ग्रामीणों के पास उपलब्ध नहीं होती। इसलिए जानकारी के लिए कृषक मेला, शिविर एक अलग ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का खुलासा कार्य होना चाहिए।

2. महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, इसलिए गाँव में जो महिलाएं स्वसहायता समूह चला रही होती हैं उनके द्वारा जानकारी दी जाए।

3. वित्त की समूचित व्यवस्था के लिए जो वित्तीय संस्थाएं विभिन्न प्रकार के सभी स्तरों पर ऋण देती हैं उनकी जानकारी भी गांव में जो कालेज एवं स्कूलों के द्वारा शिविर लगाए जाते हैं। छात्राओं के माध्यम से दी जा सकती है।

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दारोमदार जब कृषि पर ही आधारित है तो कृषि विकास के लिए सिंचाई, उत्तम बीज, खाद, विपणन, परिवहन के साधनों की समुचित व्यवस्था, भूमि सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उन्मूलन, कृषि भण्डारण की व्यवस्था इत्यादि ग्राम स्तर पर ही होना चाहिए। जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत 'कृषि विकास' योजना शुरू की गई है। विशिष्ट फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए साइल हेल्थ कार्ड की पेशकश की गई नई यूरिया नीति की घोषणा, 33 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर किसान मुआवजा, ग्राम ज्योति योजना, इसके लिए 1 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए। 17 सरकार कृषि विकास के लिए योजनाएं व तरीके अपना रही हैं पर इससे कितना लाभ कृषि कृषकों को हो रहा है। इसके लिए सरकार को एक योजना पश्चात लाभ का विश्लेषण करने के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा।

उपरोक्त वर्णित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वोपरी है क्योंकि कृषि ही ग्रामीणों के जीवन की संजीवनी बूटी है इसलिए ग्राम विकास एवं कृषि विकास के लिए सरकारी स्तर, निजी स्तर जो प्रयास किए जा रहे हैं। उनका लाभ शत-प्रतिशत कृषकों को मिल जाए तो कृषि की भूमिका में चार चाँद लग जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था विश्व में कृषि उत्पाद में अग्रणी हो जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. पंत डी.सी. - भारत में ग्रामीण विकास विश्वभारती पब्लिकेशन्स. नई दिल्ली, 2011
2. www.brainstark.com>agriculture
3. डॉ. मिश्र जयप्रकाश - कृषि अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,
4. डॉ. पंत जैसी, डॉ. मिश्रा जे. पी. - भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन
5. पब्लिकेशन, आगरा, 2015,
6. डॉ. मामोरिया चतुर्भुज, डॉ. जैन एस.सी. - भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2010
7. कृषि का महत्व एवं भूमिका |
8. www.vivacepanarama.com
9. https://mpatrika.com
10. भारतीय अर्थव्यवस्था,
11. www.krishakjagat.org
12. प्रतियोगिता दर्पण - 641 प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली, 2014,
13. hindi.indiawaterportal.org
14. https://hi.m.wikipedia.org
15. https://tejarsaval.waredpross.com 15. कृषि अर्थशास्त्र,
16. https://books.google.co.in/books
17. hi.vikaspedia.in>social-welfare
18. www.pmindia.gov.in>government.free
19. डॉ. माहेश्वरी पी.डी., डॉ. गुप्ता शीलचन्द्र - भारत में आर्थिक पर्यावरण, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2007,